ing in view the importance of such meetings. The question of further strengthening of staff in our mission to W.T.O. in Geneva will be considered on merits.

सुपर बाजार में वित्त और बिक्री विभाग का मध्यावधि मूल्यांकन

1056. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुपर बाजार के वित्त और बिक्री विभागों का कोई मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान उक्त संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक और कर्मचारियों के बीच तालमेल का अभाव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ग) सुपर बाजार एक स्वायत्तशासी सहकारी सोसायटी है। इसका अपने व्यापार के नियोजन तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्वयं का एक प्रबंध मंडल है। तथापि, भारत सरकार जनहित में इसके कार्य की समय-समय पर समीक्षा करती है तथा सुपर बाजार के लेखा परीक्षित लेखाओं को हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखती है।

गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार के लक्ष्य तथा उपब्धियां जैसी की सुपर बाजार द्वारा भेजी गई है, निम्नवत है :—

(लाख रु० में)

	1992-93	1993-94	1994-95
अनुमानित बिक्री	12333.00	13535.00	14544.00
वास्तविक बिक्री	10303.98	11520.34	13015.23
अनुमानित शुद्ध लाभ	16.90	15.73	24.75
वास्तविक शुद्ध लाभ	10.83	41.65	22.11

(घ) भारत सरकार सुपर बाजार को जनहित में विस्तार विविधीकरण तथा नवीकरण कार्यक्रम के लिए कुछ वित्तीय सहायता देती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

गुजरात में कोयले का दोहन

1057. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कोयले के दोहन के लिए केन्द्रीय सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रस्तावों का विचार या उनका अध्ययन किया है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान गुजरात में कोयले के दोहन के लिए किसी क्षेत्र के बारे में विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गुजरात में प्रति वर्ष जिला-वार कुल कितने कोयले की मांग है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1995-96 के दौरान राज्य में कोयले की समग्र मांग पूरी करने के लिए कोई उचित कदम उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) गुजरात राज्य में कोयले के भण्डार पाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) से (छ) कोयले की मांग का मूल्यांकन समग्र रूप से देश के लिए क्षेत्र-वार किया जाता है और अलग से जिला-वार मांग के अनुमानों को नहीं लगाया जाता है। को०ई०लि० स्रोतों से वर्ष 1995-96 (दिसम्बर, 1995 तक) के दौरान गुजरात राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति 11.37 मिलियन टन (अनंतिम) की गई थी। रेल या सड़क द्वारा उद्योगों को प्रस्तुत किए गये संपूर्ण कार्यक्रम को पूरा किये जाने का कोल इंडिया लिए प्रयास कर रही है। रेल द्वारा संकलन में यदि कमी होती है तो ऐसी स्थिति में उनके उपयोग न किये गये प्रयोजनों/योजनाओं के एवज में सभी उपभोक्ताओं को यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने आर्डर सड़क द्वारा बुक करा सकें। इसके अतिरिक्त कई